हिंदी सांध्य दैनिक

भवानी टाईम्स

प्रधान संपादक : चंद्रकांत खंडेलवाल, 9422831140

RNI Reg.NO.39851/1981

E-mail : bhawanitimes@gmail.com

वर्ष : 46 अंक : 14 गोंदिया, सोमवार दि. 15 जुन 2026 पृष्ठ : 04 मूल्य : 1.10 रू Post Redg.NPMFL/27/2024-2026

घायल व्यक्ति की मौत

संवाददाता / गोंदिया

देवरी थाने के तहत देवरी-आमगांव मार्ग के ग्राम डवकी में घटित सड़क दुर्घटना में घायल की उपचार के दौरान मौत हो गई. मृतक का नाम देवरी निवासी अकबर शौकत अली सैयद (55) बताया गया है. मृतक अकबर शौकत अली सैयद देवरी से डवकी गांव की ओर पैदल जा रहा था. तभी आमगांव से आ रही दोपहिया वाहन के चालक ने अपने वाहन को तेज गति से लापरवाहीपूर्वक चलाकर उसे जोरदार टक्कर मार दी. जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया था. आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

संक्षिप्त

खेत की मेड़ को लेकर विवाद, बुजुर्ग पर पत्थर से हमला

गोंदिया : अर्जुनी मोरगांव थानांतर्गत सिरोली गांव में खेत की मेड़ को लेकर हुए विवाद में एक बुजुर्ग किसान घायल हो गया. पुलिस के अनुसार, दुधराम नाजुकराम मस्के (66) अपने खेत में ट्रैक्टर से जुताई कर रहे थे. इसी दौरान उनके रिश्तेदार नीताराम नाजुकराम मस्के (62) वहां पहुंचे और मेड़ को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाते हुए विवाद शुरु कर दिया. दूधराम ने आरोपों से इंकार किया, लेकिन आरोपी ने गालीगलौज करते हुए झगड़ा किया और खेत में पड़ा एक पत्थर उठाकर उनकी ओर फेंक दिया. पत्थर दूधराम के सिर पर लगने से उन्हें गंभीर चोट आई और खून बहने लगा. आरोपी ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी. पीड़ित की शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है.

लोहे की रॉड से हमला

गोंदिया : अर्जुनी मोरगांव थाने के तहत बोरटोला/सावरटोला निवासी फिर्यादी सुभाष सदाशिव गोंधले (48) ने आरोपी विनोद सदाशिव गोंधले (50) से कहां कि तुने रखी हुई ईट मेरी जगह से बाजू में कर, मुझे कम्पाउंड करना है. जिस पर आरोपी ने तेरी काहे की जगह ऐसा कहते हुए गालीगलौज की. साथ ही लोहे की रॉड से प्रहार कर दिया. फिर्यादी की पत्नी के साथ धक्का-मुक्की कर फिर्यादी की लड़की को थप्पड़ जड़ दिया.

अवैध रेत ले जा रहे टिप्पर को पकड़ा

गोंदिया : आमगांव थाने के तहत ग्राम ननसरी परिसर में बीना रॉयल्टी के अवैध रेत ले जा रहे टिप्पर को पुलिस ने पकड़ा. इस कार्रवाई में 16 लाख रु. कीमत का टिप्पर व 12 हजार रु. कीमत की तीन ब्रास रेत ऐसे कुल 16 लाख 12 हजार रु. का माल जब्त किया गया. फिर्यादी सिपाही गौरव बुराडे की शिकायत पर पदमपुर निवासी वाहन चालक इकबाल याकुल शेख (32) व आमगांव निवासी मालिक विजय नागपुरे (52) के खिलाफ मामला दर्ज किया है. जांच हवलदार कुंभरे कर रहे हैं.

कड़े से किया प्रहार

गोंदिया : ग्रामीण थाने के तहत फुलचूर निवासी फिर्यादी बुधराम चिंधालोरे (24) व उसके मित्र के साथ फुलचूरटोला निवासी आरोपी आर्यन मौजे (18) व गणेश राऊत (32) ने बिना कारण विवाद कर गालीगलौज की. एक आरोपी ने हाथ के कड़े से प्रहार कर दिया व दूसरे आरोपी ने हाथ से मारपीट की. जिसमें फिर्यादी घायल हो गया.

कलपाथरी परियोजना के सिंचित क्षेत्र में बडी कमी

वर्षों बाद भी नहरों का निर्माण अधूरा ; किसान आज भी पानी की प्रतीक्षा में

संवाददाता / गोरेगांव

तहसील में कलपाथरी मध्यम परियोजना योजना वर्ष 1999-2000 में शुरू की गई थी। इस योजना के कारण क्षेत्र के 1,915 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी, ऐसा दावा प्रारंभ में किया गया था। आज इस परियोजना के निर्माण पर करोड़ों रुपये का धन खर्च किया जा चुका है, लेकिन इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी यह परियोजना अधूरी ही है, जिससे किसान अब नाराज़गी जताते हुए सवाल उठा रहे हैं।

कलपाथरी योजना से पूर्ण क्षमता के साथ सिंचाई की व्यवस्था क्यों नहीं हो पा रही है और यह परियोजना आखिर कब तक अंधेरे में पड़ी रहेगी, ऐसा प्रश्न पूछा

जा रहा है। इस अधूरी परियोजना के कारण वर्तमान में केवल 500 हेक्टेयर भूमि को ही सिंचाई का लाभ मिल रहा है, जबकि शेष क्षेत्र पानी से वंचित है। गोरेगांव, सडक अर्जुनी, देवरी और सालेकसा के किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2000 में यह योजना शुरू की गई थी। इसके लिए कलपाथरी और आसपास के गांवों के किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया गया था तथा कलपाथरी गांव का पुनर्वास भी किया गया था। लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के कारण यह महत्वाकांक्षी परियोजना आज भी अधर में लटकी हुई है।

इस योजना के माध्यम से गांवों में पानी की आपूर्ति की जानी थी। संबंधित गांव भूमि स्तर से ऊंचाई पर स्थित होने के कारण वहां पानी पहुंचाने के लिए नहरों का निर्माण किया गया था। लेकिन रखरखाव के अभाव में ये नहरें अब पूरी तरह जर्जर और बदहाल हो चुकी हैं। परिणामस्वरूप, मूल 1,915 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की तुलना में आज वास्तव में केवल 500 हेक्टेयर क्षेत्र में ही सिंचाई हो पा रही है। इस परियोजना के कारण अपने क्षेत्र में हरित क्रांति आने का सपना देखने वाले स्थानीय किसान आज भी इस परियोजना के पूरा होने की उम्मीद में प्रशासन की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं।

338 परियोजना प्रभावितों का पुनर्वास

गोरेगांव तहसील की कलपाथरी मध्यम परियोजना के अंतर्गत 556.14 हेक्टेयर प्रभावित क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत 24 फरवरी 2000 को एक अधिसूचना जारी की गई थी। भूमि अधिग्रहण नियमों के अनुसार, इस प्रभावित क्षेत्र के 3 गांवों के कुल 338 खातेदारों को गोरेगांव शहर के निकट भूमि के भूखंड (प्लॉट) आवंटित करके उनका पुनर्वास किया गया था, ऐसी जानकारी सामने आई है।

पागल कुत्ते का आतंक; ११ लोग घायल

सिल्ली की घटना : ग्रामीणों में भय

संवाददाता / तिरोड़ा

तहसील के सिल्ली गांव में पागल कुत्ते का आतंक जारी है। 13 जून को गांव में एक पागल कुत्ते ने लगभग 11 लोगों को काटकर घायल कर दिया। इस घटना से गांव में कुत्तों का डर बढ़ गया है और ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया है। ग्राम पंचायत प्रशासन से तत्काल उपाय कर स्थिति को नियंत्रित करने की मांग की जा रही है।

सिल्ली गांव में पिछले कुछ दिनों से आवारा कुत्तों का उत्पात बढ़ गया है। सड़कों पर झुंड बनाकर रहने वाले कुत्ते नागरिकों के लिए खतरनाक साबित होने लगे हैं। 13 जून को सुबह लगभग 6 बजे एक पागल कुत्ते ने करीब 11 लोगों को काटकर घायल कर दिया। इस घटना से गांव में अफरा-तफरी मच गई। खेतों की ओर जा रहे लोगों पर उसने अचानक हमला कर उन्हें घायल कर दिया। इनमें छोटे बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए तिरोड़ा ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रामीणों ने मांग की है कि ग्राम पंचायत प्रशासन तुरंत आवारा कुत्तों पर नियंत्रण करे।

गांव में पिछले कुछ दिनों से आवारा कुत्तों का उपद्रव बढ़ गया है। इस घटना के बाद ग्रामीण भारी दहशत में हैं। बच्चे घर से बाहर निकलने से डर रहे हैं। प्रशासन को इस मामले पर तुरंत ध्यान देकर इन पागल कुत्तों को पकड़ना चाहिए और ग्रामीणों को राहत प्रदान करनी चाहिए।

- सुभाष वडीचार, सरपंच

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व तैयारी बैठक उत्साहपूर्वक संपन्न!

२१ जून को भव्य 'योग उत्सव'

संवाददाता / गोंदिया

'हर गली, हर द्वार - योग बने जनअधिकार' की संकल्पना को साकार करते हुए नगर योग उत्सव समिति, गोंदिया की ओर से आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 की पूर्वतैयारी संबंधी महत्वपूर्ण बैठक आज योग भवन, सिविल लाइन, गोंदिया में उत्साहपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई।

विश्वभर में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। गोंदिया में पिछले 10 वर्षों से नगर परिषद स्टेडियम में शासकीय, अर्धशासकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक तथा विभिन्न योग संस्थाओं के संयुक्त सहयोग से भव्य 'योग उत्सव' आयोजित किया जाता रहा है और यह उपक्रम जिले में स्वास्थ्य जागरूकता का

प्रेरणादायी उत्सव बन गया है। बैठक में योग उत्सव 2026 के सफल आयोजन के लिए विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। इसमें मुख्य रूप से जनसंपर्क, प्रचार-प्रसार, स्वयंसेवक प्रबंधन, संस्थागत सहभागिता, नागरिक जागरूकता, शासकीय समन्वय तथा कार्यक्रम की विभिन्न जिम्मेदारियों के वितरण पर विचार किया गया।

इस अवसर पर उपस्थित सभी संस्थाओं के पदाधिकारियों ने गोंदिया जिले के प्रत्येक वार्ड, मोहल्ले, विद्यालय, महाविद्यालय, संस्था और परिवार तक योग का संदेश पहुंचाने का संकल्प व्यक्त किया। नगर योग उत्सव समिति की ओर से सभी नागरिकों से अपील की गई कि वे 21 जून को सुबह 6:00 बजे नगर परिषद स्टेडियम, गोंदिया में आयोजित अंतरराष्ट्रीय योग दिवस एवं योग उत्सव 2026 में अपने परिवार सहित बड़ी संख्या में उपस्थित रहें। समिति की ओर से यह आग्रह किया गया है।

अग्निरोधी यंत्र गायब

गोरेगांव : अनेक शाला, ट्यूशन कक्षा व हॉस्पिटल में लगने वाली आग से सर्वसामान्य को नाहक जान गंवानी पड़ती है. अनेक शालाओं में अग्निशमन यंत्र ही नहीं है. जिससे शालाओं में अध्ययनरत बड़ी संख्या में विद्यार्थियों पर खतरा मंद्रा रहा है. कुछ शालाओं में यह यंत्र है. लेकिन उन शालाओं के अग्निशमन यंत्रों की अवधि समाप्त हो गई है.

छह नदियां बनती हैं आफत, प्रशिक्षण, जागरूकता व कार्यशालाओं का आयोजन

९६ गांव रेड जोन में, मानसून में बैकवाटर का खतरा

संवाददाता / गोंदिया

जिले में छोटी-बड़ी 6 नदियां हैं. इन नदियों को जीवनदायिनी कहा जाता है. लेकिन, मानसून के दौरान ये खतरनाक रूप ले लेती हैं. इन नदियों के किनारे बसे 96 गांवों के नागरिकों को 'बैकवाटर' के खतरे का सामना करना पड़ता है.

हर साल इनमें से आधे गांवों में बाढ़ का पानी घुस जाता है.

फिलहाल मानसून के सक्रिय होने में देरी हो रही है. 12 जून की शाम को बारिश हुई. नदियां सूखी हैं. छोटे-बड़े नालों का पानी वैनगंगा, गाढ़वी, बाघ, चुलबंद, बहेला, पांगोली नदियों में बहता है. गोंदिया जिले की सबसे बड़ी नदी वैनगंगा है. नदी का तल गहरा होने के कारण आमतौर पर इस नदी का पानी गांवों में नहीं आता है. लेकिन, मानसून के दौरान अन्य नदियां जिले के नागरिकों के लिए खतरे का सबब बन जाती हैं. सालेकसा, आमगांव और गोंदिया तहसील के कई गांव बाघ और पांगोली दो नदियों से आने वाले बाढ़ के पानी से प्रभावित होते हैं. गाढ़वी, चुलबंद, बहेला नदियों का पानी सड़क अर्जुनी और अर्जुनी मोरगांव तहसील के गांवों में प्रवेश करता है.

नन्हें क्रिकेटरों ने किया पौधों का रोपण

गोंदिया : बिग बॉस की ओर से शास्त्री वार्ड स्थित एएस क्रिकेट अकादमी तथा बिग बॉस टर्फ परिसर में विविध प्रजाति के पौधे लगाए गए. अकादमी के नन्हें क्रिकेटरों ने वृक्षारोपण किया. क्रीड़ा संगठक अनिल सहारे ने खिलाड़ियों से कहा कि, इस समय सभी को गर्मी का अनुभव करना पड़ रहा है. सभी को अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए.

वृक्षारोपण के फायदे और पेड़ों के संवर्धन संबंधी जानकारी दी. सभी बच्चों ने पेड़ों की सुरक्षा का संकल्प लिया. नीम, कदम, आंवला, गुलमोहर, सेल्वेट, उम्बर आदि के पेड लगाए गए.

पुरुषोत्तम मास एवं सोमवती अमावस्या पर आज होगा भव्य महा गंगा आरती एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम

संवाददाता / तिरोड़ा

पुरुषोत्तम मास एवं सोमवती अमावस्या के पावन अवसर पर तपोवन धाम समिति, वेनगंगा घाट, कवलेवाड़ा द्वारा सोमवार को भव्य महा गंगा आरती, 1008 दीपदान तथा 51 वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। धार्मिक आस्था और पर्यावरण संरक्षण को समर्पित यह विशेष आयोजन दोपहर 4 बजे से तपोवन धाम, वेनगंगा घाट, कवलेवाड़ा में संपन्न होगा।

आयोजकों के अनुसार कार्यक्रम में श्रद्धालुओं को वेनगंगा तट पर आयोजित दिव्य महा गंगा आरती में सहभागी होने का अवसर मिलेगा। इसके साथ ही 1008 दीपों के सामूहिक दीपदान के माध्यम से भक्तजन पुण्य लाभ अर्जित करेंगे। पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के उद्देश्य से 51 पौधों का वृक्षारोपण भी किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन तपोवन धाम के प्रेरणास्रोत एवं प्रख्यात कथावाचक पंडित डॉ. नंदकिशोर मिश्रा (बेरीडीपार वाले) के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। उनके सान्निध्य में आयोजित होने वाला यह धार्मिक अनुष्ठान क्षेत्र के श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा।

तपोवन धाम समिति ने क्षेत्र के सभी श्रद्धालुओं, भक्तों एवं नागरिकों से कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की है। समिति का कहना है कि यह आयोजन धार्मिक आस्था के साथ-साथ प्रकृति संरक्षण का संदेश देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।

पुरुषोत्तम मास और सोमवती अमावस्या के शुभ संयोग पर आयोजित यह भव्य कार्यक्रम क्षेत्र में आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण करेगा तथा समाज को धर्म एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

शिर्डी में आयोजित राज्य स्तरीय वुशू जज एवं कोच प्रशिक्षण शिविर में गोंदिया जिले का शानदार प्रदर्शन

२५ जिलों के १४६ प्रशिक्षकों ने लिया भाग तिरोड़ा के खिलाड़ियों ने बढ़ाया जिले का मान

संवाददाता / तिरोडा

ऑल महाराष्ट्र वुशू एसोसिएशन की मान्यता तथा अहमदनगर जिला एमेच्योर वुशू एसोसिएशन के तत्वावधान में शिर्डी स्थित साई पालकी निवारा, निमगांव में 12 से 15 जून 2026 तक राज्य स्तरीय वुशू जजेस ट्रेनिंग एवं सर्टिफिकेशन कोर्स का सफल आयोजन किया गया। चार दिनों तक चले इस प्रशिक्षण शिविर में महाराष्ट्र के 25 जिलों से कुल 146 रेफरी, जज, प्रशिक्षक एवं कोचों ने सहभागिता दर्ज कराई। शिविर में वुशू खेल से संबंधित नवीनतम नियमों, रेफरी की तकनीकी जिम्मेदारियों, टूर्नामेंट प्रबंधन, स्कोरिंग प्रणाली, खिलाड़ियों के मूल्यांकन तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू आधुनिक नियमों का विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। विशेष रूप से वुशू की 'ताउलू' एवं 'सांडा' श्रेणियों की तकनीकी बारीकियों से प्रतिभागियों को अवगत कराया गया. प्रशिक्षण कार्यक्रम में अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी एवं राष्ट्रीय रेफरी (एसजीएफआई एवं एनआईएस कोच) लक्ष्मण उदमले, दिनेश माली, अविनाश

पाटिल तथा दीपक भिसेन ने मुख्य प्रशिक्षक के रूप में मार्गदर्शन किया। वहीं पांडुरंग अंभोरे, आनंद भुसारी, विजयकुमार खंडार, महेश इंदापुरे, सुरेश चौधरी, अनिल खराडे, दत्तात्रय पाटिल एवं उत्तम उगाडे का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहा।

इस प्रतिष्ठित शिविर में गोंदिया जिले के आधिकारिक वुशू संघ के प्रतिनिधियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जिले का गौरव बढ़ाया। तिरोड़ा तहसील से दीपक घरजारे, विकेश मेश्राम, चंद्रप्रकाश प्रजापति, अमन नंदेश्वर एवं राजेश वरठे ने ताउलू और सांडा स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन कर सभी का ध्यान आकर्षित किया। गोंदिया जिले के खिलाड़ियों एवं प्रशिक्षकों की इस उपलब्धि पर तिरोड़ा-गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक विजय रहांगडाले सहित अनेक जनप्रतिनिधियों, खेल अधिकारियों तथा सामाजिक क्षेत्र की गणमान्य हस्तियों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। खिलाड़ियों की इस सफलता से जिले के खेल प्रेमियों में उत्साह का माहौल है तथा वुशू खेल को नई पहचान मिली है।

स्मार्ट ग्राम पंचायत गंगाझरी में हुए कामों में भ्रष्टाचार !

गोंदिया : स्मार्ट ग्राम पंचायत गंगाझरी में विभिन्न विकास कामों पर करोड़ों रुपयों का भ्रष्टाचार करने का आरोप शिकायतकर्ता आंदोलनकारियों ने करते हुए जांच की मांग की है। जिसको लेकर 8 जून से आंदोलन शुरू किया है। जिसे देखते हुए जिला परिषद प्रशासन ने जांच समिति का गठन किया है।

इस संदर्भ में जानकारी दी गई कि गोंदिया तहसील अंतर्गत गंगाझरी ग्राम पंचायत को शासन की ओर से स्मार्ट ग्राम पंचायत से पुरस्कृत किया है। लेकिन ग्राम के शिकायतकर्ता हेमंत बघेले, सन्नी बघेले, रामसिंग पंधरे, नानाजी वाहने, चेतन लिल्हारे, अर्जुन नागभिरे, गणपत टेकाम, योगेश पगरवार आदि ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। आखिरकार जिला परिषद ग्राम पंचायत विभाग ने जांच समिति का गठन कर जांच के आदेश दिए हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि जांच रिपोर्ट 7 दिन के भीतर जिला परिषद पंचायत विभाग को प्रस्तुत करें। इस तरह का पत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने 12 जून को जारी किया है।

संपादकीय

महंगा होता इलाज

ऐसे वक्त में जब महंगाई के कारण जीवनयापन कठिन हो रहा है, नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एन.पी.पी.ए. द्वारा कुछ जीवनरक्षक दवाओं की कीमतों में वृद्धि की इजाजत देना कमजोर वर्गों के लिए 'कंगाली में आटा गीला होना' जैसा है। एन.पी.पी.ए. द्वारा जिन दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी की इजाजत दी गई है, उनमें कुछ कैंसर की दवाएं, एंटी-टेटनस सीरम और बच्चों के टीकों की कीमतों में पचास प्रतिशत की वृद्धि शामिल है। निश्चय ही यह फैसला पब्लिक हेल्थ पॉलिसी से जुड़ी विसंगतियों को दर्शाता है। निस्संदेह, भारत जैसे देश में जरूरी दवाओं को सस्ता रखना बेहद जरूरी है, जहां बहुत से परिवार इलाज का खर्च अपनी जेब से उठाते हैं। वहीं दूसरी ओर, यह भी जरूरी है कि जीवनरक्षक दवाओं की बाजार में सहज उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। बहुत संभव है कि अमेरिका-ईरान युद्ध संकट से बाधित आपूर्ति श्रृंखला के चलते कुछ दवाइयों व टीकों की कीमतों में बढ़ोतरी को तार्किक बताया जाए, लेकिन चिकित्सा व्यवस्था में अमीर-गरीब की आर्थिक क्षमता को लेकर उठने वाले सवाल न्यायसंगत ही कहे जाएंगे। दरअसल, एन.पी.पी.ए. ने दवाओं की कमी और बढ़ती लागत को कीमत वृद्धि का कारण बताया है। दलील दी गई कि यदि दवा बनाने वाली कंपनियां इनकी उत्पादन लागत नहीं निकाल पाती हैं तो वे खुले बाजार में इन दवाइयों की आपूर्ति बंद कर सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद गरीब तबके की सीमाओं और आर्थिक स्थिति का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

बहरहाल, इस बाबत दी गई दलीलों के बावजूद एक सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता कि इस देश में करोड़ों लोग बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं का खर्च उठाने के लिए संघर्ष करते हैं। निर्विवाद रूप से कैंसर के इलाज और बच्चों को बीमारियों से बचाने वाली दवाइयों की कीमतों में पचास फीसदी बढ़ोतरी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को गहरे आर्थिक संकट में डाल सकती हैं। मरीजों के लिए इलाज के खर्च में दवाओं के अलावा, रोग की जांच, दूर-दराज के क्षेत्रों से बड़े अस्पतालों तक की यात्रा, अस्पताल में भर्ती होने का खर्च तथा इस दौरान होने वाली आय की हानि भी शामिल होती है। ऐसे में दवाओं की कीमतों में वृद्धि का अतिरिक्त बोझ उन्हें इलाज और जीवित रहने के बीच कई मुश्किल फैसले लेने को मजबूर कर सकता है। इसका समाधान किफायती होने और उपलब्धता के बीच चयन करने में नहीं है, बल्कि एक ऐसा तंत्र विकसित करने में है, जो दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। सरकार को सरकारी अस्पतालों के लिए दवा खरीद व्यवस्था को पारदर्शी व मजबूत बनाने की जरूरत है। उसे सरकारी अस्पतालों के जरिये बिना किसी बाधा के दवाइयों की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। साथ ही, स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में जरूरी दवाइयों को भी शामिल करना चाहिए, जिससे खास सब्सिडी के जरिये गरीब मरीजों को अचानक कीमतों में बढ़ोतरी से बचाया जा सके। इसके अलावा, दवाइयों की कीमतों से जुड़ी नीतियों की समय-समय पर समीक्षा भी होनी चाहिए, जिससे पता चल सके कि वास्तव में दवाइयों की लागत में कितनी वृद्धि हुई है।

350 भूखंडधारकों को एक महीने में कागजात देने के आदेश

शेष लंबित मामले दो माह में निपटाएं : फ्री-होल्डधारकों को मिलेंगे प्रॉपर्टी कार्ड : जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित बैठक में पालकमंत्री पंकज भोयर ने अधिकारियों को दिए निर्देश

वर्धा : शहर के रामनगर क्षेत्र में वर्षों से लीज भूमि पर रहने वाले नागरिक लंबे समय से मालिकाना पत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे. राज्य सरकार द्वारा इन भूखंडों को फ्री-होल्ड घोषित किए जाने के बाद भी भूखंडधारकों को मालिकाना हक के संपत्ति पत्रक (प्रॉपर्टी रिकॉर्ड) मिलने में हो रही देरी पर पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर ने नाराजगी जताई है. इस संबंध में पालकमंत्री ने भूमि अभिलेख विभाग को सभी पात्र फ्री-होल्डधारकों को उनके भूखंडों के मालिकाना हक के पत्रक तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए. इससे रामनगर के ३५० फ्री। होल्डधारकों को मालिकाना हक मिलने का रास्ता साफ हो गया.

इस संबंध में पालकमंत्री डॉ. भोयर ने जिलाधिकारी का यालय के सभागार में नगर परिषद, राजस्व विभाग और भूमि अभिलेख विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की. बैठक में उन्होंने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि अगले एक माह के भीतर ३५० भूखंडधारकों को भोगवटदार वर्ग-१ के संपत्ति पत्रक वितरित किए जाएं तथा शेष लंबित मामलों का निपटारा आगामी दो माह में किया जाए.

बैठक में वर्धा नगर परिषद के उपाध्यक्ष प्रदीपसिंह ठाकर. निवासी उपजिलाधिकारी संजीव जाधवर, मुख्याधिकारी विजय देशमुख, सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता एकनाथ टिकले, भूमि अभिलेख विभाग के उपअधीक्षक सुनील बन सहित रामनगर के अनेक फ्री-होल्डधारक नागरिक उपस्थित थे. डॉ. भोयर ने कहा कि रामनगर के नागरिक कई वर्षों से लीज भूमि पर रह रहे थे. इन परिवारों को स्थायी मालिकाना अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने सरकारी स्तर पर लगातार प्रयास और पत्राचार किया. इसी प्रयास के परिणामस्वरूप सरकार ने रामनगर के लीजधारकों के भूखंड फ्री-होल्ड करने का निर्णय लिया.

नगर परिषद द्वारा भी संबंधित भखंडधारकों के फ्री-होल्ड आदेश जारी किए जा चुके हैं. फ्री-होल्ड प्रक्रिया पूरी होने के बाद नागरिकों को मालिकाना हक के दस्तावेज उपलब्ध होना अत्यंत आवश्यक है. इसलिए भूमि अभिलेख विभाग को समयबद्ध तरीके से सभी आवश्यक रिकॉर्ड तैयार कर वितरित करने की जिम्मेदारी निभानी होगी. बैठक में पालकमंत्री ने नगर परिषद के मुख्याधिकारी को भी निर्देश दिए कि रामनगर के नागरिकों की अन्य प्रशासनिक समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाए.

समाधान की दिशा में आगे बढ़ा मामला

रामनगर के नागरिक लंबे समय से भूमि अभिलेख विभाग से मालमत्ता पत्रक जारी करने की मांग कर रहे थे. पालकमंत्री द्वारा संबंधित विभागों की संयुक्त बैठक लेने और स्पष्ट समयसीमा तय करने से अब यह मामला समाधान की दिशा में आगे बढ़ गया है. इससे सैकड़ों परिवारों को अपने भूखंडों पर कानूनी मालिकाना हक का प्रमाण मिलने का रास्ता साफ हो गया है.

७.७४ करोड़ का मुआवजा किसानों के खातों में !

विधायक वानखेड़े के प्रयासों से आर्वी में औद्योगिक क्रांति का आगाज

संवाददाता । वर्धा

आर्वी विधानसभा क्षेत्र में औद्योगिक क्रांति के दरवाजे खुल गए हैं. इसके पहले चरण में विधायक सुमित वानखेड़े के प्रयासों से एमआईडीसी की नींव रखी गई थी. अब जमीन अधिग्रहण के मुआवजे की राशि सीधे किसानों के खाते में भी जमा कर दी जाएगी.

आर्वी में एमआईडीसी की स्थापना हेतु अधिगृहीत की गई भूमि के मुआवजे के रुप में ७२ किसानों को १४३.६१ हेक्टेयर भूमि के बदले कुल ७ करोड़ ७४ लाख ३८ हजार ६६५ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है. यह राशि शीघ्र चरणबद्ध तरीके से किसानों के खाते में जमा होगी. इस संबंध में विधायक सुमित वानखेड़े के हाथों किसानों को आदेश पत्र सौंपा गया है. इस समय एसडीओ विश्वास शिरसाट और तहसीलदार हरीश काले उपस्थित थे. प्रथम चरण के अंतर्गत ४ करोड़ ९९ लाख ३० हजार ७९८ रुपए तथा द्वितीय चरण के अंतर्गत २ करोड़ ७५ लाख ७ हजार ८६७ रुपयों का समावेश है. एमआईडीसी के लिए विधायक वानखेड़े ने प्रारंभ से ही प्रशासनिक स्तर पर लगातार प्रयास किए. १३ जून २०२३ को मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की उपस्थिति में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में उन्होंने इस परियोजना को गति देने की जोरदार मांग उठाई. इसके बाद ८ अगस्त २०२४ को उन्होंने तत्कालीन जिलाधिकारी राहुल कर्डिले से मुलाकात कर एमआईडीसी के लिए 'त्वरित प्रत्यक्ष खरीद' पद्धति के माध्यम से भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को राजस्व विभाग द्वारा शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया इतना ही नहीं, २० दिसंबर २०२४ को एमआईडीसी के सीईओ आर. वेलारसू से मुलाकात कर परियोजना से जुड़ी तकनीकी एवं प्रशासनिक अड़चनों को दूर करने के लिए भी विशेष प्रयास किए.

पुलिस फोर्स ने वर्ल्ड ब्लड डोनर-डे पर लगाया रक्तदान शिविर

४८६४ ने दिया रक्तदान सर्वश्रेष्ठ दान का संदेश

गढ़चिरोली : गढ़चिरोली पुलिस बल कीओर से पुलिस दादालोरा खिड़की एवं 'प्रोजेक्ट उड़ान' के तहत विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर रविवार को जिला मुख्यालय सहित छह स्थानों पर रक्तदान शिविर आयोजित किया गया. इस अभियान में कुल ४,८६४ रक्तदाताओं ने रक्तदान कर 'रक्तदान सर्वोत्तम दान' का संदेश दिया.

जिले में रक्त की आवश्यकता को पूरा करने, रक्तदान के प्रति जनजागरुकता बढ़ाने तथा रक्तदाताओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने के उद्देश्य से यह शिविर आयोजित किया गया. गढ़चिरोली पुलिस बल ने जिला सामान्य अस्पताल रक्त केंद्र, गढ़चिरोली तथा उप-जिला अस्पताल रक्त केंद्र, अहेरी के सहयोग से पांडु आलम सभागृह, पुलिस मुख्यालय गढ़चिरोली, उप-मुख्यालय प्राणहिता एवं उप-विभागीय पुलिस अधिकारी कार्यालय सिरोंचा सहित विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाए. इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन बी.जे., उप-विभागीय पुलिस अधिकारी अजय कोकाटे, संदेश नाइक सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी, पुलिस बल, सीआरपीएफ, एसआरपीएफ जवान तथा बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे.

इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक एम. रमेश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (अभियान) कार्तिक मधीरा, सहायक पुलिस अधीक्षक अनिकेत हिरदे, उप पुलिस अधीक्षक (अभियान) विशाल नागरगोजे, अतिरिक्त जिला सर्जन डॉ. छाया उइके, मुख्य चिकित्सा अधिकारी पुलिस अस्पताल सुनील मडावी, आदिवासी कल्याण समिति इंटरनेशनल, नागपुर के जिला अध्यक्ष राजीव वरभे, स्पेशल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, शालिनीताई मेघे ब्लड बैंक नागपुर अश्विन राडके मौजूद थे. इस प्रोग्राम की सफलता के लिए सभी सब-डिविजनल पुलिस ऑफिसर, पोस्ट/सब-पोस्ट/पीओएमसी के ऑफिसर-इन-चार्ज के साथ-साथ सिविल एक्शन ब्रांच के सब-इंस्पेक्टर चंद्रकांत शेलके, पुलिस वेलफेयर ब्रांच के ऑफिसर-इन-चार्ज सब-इंस्पेक्टर नरेंद्र पिवाल, पब्लिक रिलेशन ब्रांच के ऑफिसर-इन-चार्ज सब-इंस्पेक्टर प्रतीक भदाने और सभी ब्रांच के ऑफिसर और कर्मचारियों के साथ-साथ डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल गढ़चिरौली की पूरी टीम ने बहुत मेहनत की.

पुल के लिए नहीं हटने देंगे अपनी दुकानें

भामरागढ़ : तहसील मुख्यालय से सटी पर्लकोटा नदी पर पिछले पांच वर्षों से पुल निर्माण कार्य जारी है. इस पुल निर्माण के कारण मुख्य बाजार क्षेत्र के बायी ओर स्थित 34 व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा.

प्रभावित व्यापारियों ने पूर्व में हुई नापजोख के आधार पर बिना किसी आपत्ति के अपनी दुकानें और जमीन खाली कर दी थी. लेकिन अब नई नापजोख कर सड़क को दूसरी दिशा में मोड़ने तथा दायी ओर की दुकानों को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है. इसके विरोध में व्यापारियों ने अब एकजुटता दिखाते हुए पुल निर्माणकार्य के लिए दुकानों की बलि नहीं देने का निर्णय लिया है. यह जानकारी व्यापारियों ने पत्रकार परिषद में दी. व्यापारियों ने बताया कि पुल निर्माण शुरु होने से पहले मुख्य बाजार क्षेत्र में नापजोख की गई थी. इसमें बायी ओर की 34 दुकानों के प्रभावित होने की बात तय हुई थी. इसके बाद उन्होंने दुकानें खाली कर वैकल्पिक व्यवस्था स्वीकार कर ली.

ओबीसी आरक्षण को लेकर विसापुर ग्रा.पं. में हंगामा

संवाददाता । बल्लारपुर

तहसील की सबसे बड़ी विसापुर ग्राम पंचायत के सदस्य पदों के आरक्षण निर्धारण को लेकर ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी के लिए केवल एक सीट आरक्षित किए जाने के मुद्दे पर नागरिकों ने तीव्र नाराजगी व्यक्त करते हुए सभा में जोरदार हंगामा किया.

विसापुर ग्राम पंचायत चुनाव के लिए के छह प्रभागों के १७ सदस्य पदों के आरक्षण निर्धारण के लिए विशेष ग्राम सभा आयोजित की गई थी. गुरुवार को आयोजित सभा में प्राधिकृत अधिकारी सुजीत चौधरी ने जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति के लिए चार, अनुसूचित जनजाति के लिए तीन तथा ओबीसी वर्ग के लिए केवल एक सीट आरक्षित रहने की जानकारी दी. इसके बाद सभा में भारी हंगामा हुआ और बैठक स्थगित करनी पड़ी.

इसके बाद शुक्रवार दोपहर पुनः सभा आयोजित की गई. ओबीसी समाज को अपेक्षित प्रतिनिधित्व नहीं मिलने के मुद्दे पर एक बार फिर माहौल गर्मा गया. नागरिकों, संभावित उम्मीदवारों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रशासन के समक्ष आपत्ति दर्ज कराते हुए आरक्षण प्रक्रिया पर नाराजगी जताई. स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस निरीक्षक बिपिन इंगले के नेतृत्व में भारी पुलिस बल तैनात था.

इस अवसर पर नायब तहसीलदार महेंद्र फुलझेले, नायब तहसीलदार विनोद निखाते, समूह विकास अधिकारी धनंजय सालवे, ग्राम राजस्व अधिकारी आरती दुलत, ग्राम पंचायत अधिकारी गणेश कोकोड़े, ग्राम पंचायत प्रशासक वर्षा कुलमेथे तथा उपसरपंच अनेकश्वर मेश्राम सहित ग्रामवासी उपस्थित थे. अधिकारियों ने कहा कि प्रक्रिया न्यायालय तथा राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार ही की गई है.

मुंबई की कंपनी को मत्स्य व्यवसाय का ठेका, मछुआरे करेंगे आंदोलन

अधिकारों और आजीविका पर हमला करने का लगाया आरोप

संवाददाता । सेलू

बोर जलाशय में मत्स्य व्यवसाय करने का ठेका मुंबई की एक कंपनी को देने से स्थानीय मछुआरों में असंतोष व्याप्त हो गया है. वर्षों से इस जलाशय पर निर्भर सैकड़ों परिवारों का आरोप है कि उनके अधिकारों और आजीविका पर सीधा हमला किया गया है.

मछुआरों के अनुसार, बोर जलाशय में मत्स्य व्यवसाय से जुड़े ठेकों की प्रक्रिया पहले जिला स्तर पर होती थी, जिससे स्थानीय सहकारी संस्थाओं को रोजगार और व्यवसाय के अवसर मिलते थे. लेकिन इस बार कथित तौर पर परंपरा और स्थानीय हितों की अनदेखी करते हुए मुंबई स्थित मे. अमय मल्टी सोल्यूशन प्रा. लि. को ठेका दे दिया गया, जिससे पूरे क्षेत्र में असंतोष है. मछुआरों का आरोप है कि इस पूरे मामले में बड़ा आर्थिक लेन-देन और राजनीतिक हस्तक्षेप किया गया है.

मछुआरों का कहना है कि कमीशनखोरी के लालच में यह करार हुआ है. मछुआरों का कहना है कि बोर जलाशय केवल जलस्रोत नहीं, बल्कि सैकड़ों परिवारों की जीवनरेखा है. इसी जलाशय से मिलने वाली आय पर अनेक परिवारों का घर चलता है. आरोप है कि ठेका प्राप्त कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा स्थानीय मछुआरों को जलाशय में मछली पकड़ने से रोका जा रहा है, जिससे उनका रोजगार और भरण-पोषण गंभीर संकट में पड़ गया है. ग्रामीण रोजगार और स्थानीय विकास के बड़े-बड़े दावे करने वाली व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं. लोगों का कहना है कि जिस बोर जलाशय को स्थानीय विकास और रोजगार का केंद्र बनाने के वादे किए गए थे, उसी को लेकर अब स्थानीय लोगों के अधिकारों को कुचलकर बाहरी कंपनी को फायदा पहुंचाया जा रहा है. चेतावनी दी गई है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो बोर जलाशय परिसर में परिवारों सहित व्यापक आंदोलन छेड़ा जाएगा. मुंबई की कंपनी का ठेका निरस्त करने की भी मांग की गई है.

५०००० के इलेक्ट्रिक वायर की चोरी मामले में ३ आरोपी गिरफ्तार

ब्रह्मपुरी : स्थानीय पुलिस ने हलदा गांव में एक घर के आंगन से ५० हजार रु. से अधिक मूल्य के इलेक्ट्रिक सामान की चोरी करने वाले अंतर-तहसील गिरोह का २४ घंटे के भीतर पदार्फाश कर दिया. इस कार्रवाई में पुलिस ने ३ आरोपियों को गिरफ्तार किया है. चोरी में इस्तेमाल किए गए चारपहिया और दोपहिया वाहन समेत कुल ३ लाख ६० हजार रु. का माल जब्त किया गया.

नान्होरी (ता. ब्रह्मपुरी) निवासी एवं इलेक्ट्रिक कॉन्ट्रेक्टर गणेश मिसार (३६ वर्ष) ने अपने ठेके के कामों के लिए लगभग २ किलोमीटर लंबा इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ५० किलो स्टे-वायर तथा ५० किलो जीआई वायर (कुल कीमत लगभग ६० हजार रु.) हलदा गांव में मुन्ना भोयर के घर के सामने आंगन में रखा था. ११ जून २०२६ को मुंह पर कपड़ा बांधकर आए तीन अज्ञात व्यक्तियों ने यह पूरा सामान चोरी कर लिया.

गणेश मिसार की शिकायत पर ब्रह्मपुरी थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा ३०३ (२) एवं ३(५) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरु की गई. पुलिस निरीक्षक प्रमोद बानबले के मार्गदर्शन में हवलदार मुकेश गजबे ने जांच करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर नान्होरी निवासी संदिग्ध राकेश उर्फ गोलू भोयर को हिरासत में लिया. पूछताछ के दौरान उसने अपराध स्वीकार कर अपने दो अन्य साथियों के नाम बताए. राकेश की निशानदेही पर पुलिस ने मयूर उर्फ गोलू शेंडे (२५, निवासी नान्होरी, ब्रह्मपुरी) तथा विजयकुमार मेडपल्लीवार (३८, निवासी सिंगापुर, पोस्ट कवठी, ता. सावली, जिला चंद्रपुर) को गिरफ्तार किया.

आरोपियों के कब्जे से चोरी किया गया पूरा माल बरामद कर लिया गया है. साथ ही चोरी का माल ले जाने के लिए इस्तेमाल किए गए वाहन भी जब्त किए गए हैं. इसमें चौपहिया क्रमांक एमएच-३४ बीजेड-००१७ (कीमत ३ लाख रुपए) तथा मोटरसाइकिल क्रमांक एमएच-३४ बीवाई-९५०८ (कीमत ४० हजार रुपए) शामिल है. यह कार्रवाई चंद्रपुर के पुलिस अधीक्षक आयुष नोपानी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, उपविभागीय पुलिस अधिकारी (ब्रह्मपुरी) दिनकर ठोसरे तथा पुलिस निरीक्षक प्रमोद बानबले के मार्गदर्शन में ब्रह्मपुरी पुलिस थाना के अपराध खोज पथक (डीबी टीम) के सहायक पुलिस निरीक्षक मनोज खडसे, पुलिस हवलदार मुकेश गजबे, पुलिस कर्मचारी प्रवीण भिवगड़े, नीलेश तुमसरे, इरशाद खान, स्वप्निल पलसपगार तथा वशिष्ठ रंगारी ने की.

ई-लाइब्रेरी को छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम देने की मांग

ब्रह्मपुरी : शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक परिसर स्थित प्रशासनिक कार्यालय के पीछे शुरु की गई ई-लाइब्रेरी को 'छत्रपति शिवाजी महाराज ई-ग्रंथालय' नाम दिए जाने की मांग शिवसेना की ओर से की गई है. इस संबंध में उपविभागीय अधिकारी, नगर परिषद के मुख्याधिकारी तथा नगराध्यक्ष योगेश मिसार को ज्ञापन सौंपा गया.

ज्ञापन में कहा गया है कि ब्रह्मपुरी शहर में शुरु की गई ई-लाइब्रेरी विद्यार्थियों एवं आम नागरिकों के ज्ञानवर्धन के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो रही है. छत्रपति शिवाजी महाराज केवल एक महान योद्धा ही नहीं थे, बल्कि सभी वर्गों के लोगों को न्याय देने वाले कुशल प्रशासक, दूरदर्शी शासक तथा ज्ञान के संरक्षक भी थे. उनके विचारों और कार्यों की प्रेरणा से महात्मा ज्योतिराव फुले, छत्रपति शाहू महाराज तथा भारतरत्न नगराध्यक्ष योगेश मिसार को ज्ञापन सौंपते अमोल माकोडे, संजय पारटवार, नरेंद्र नरड डॉ. बाबासाहब आंबेडकर जैसे महापुरुषों ने समाज परिवर्तन का कार्य किया. ई-लाइब्रेरी का मुख्य उद्देश्य डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना तथा ज्ञान का प्रसार करना है. इस ग्रंथालय को 'छत्रपति शिवाजी महाराज ई-ग्रंथालय' नाम दिया जाता है तो यह विद्यार्थियों और नागरिकों के लिए प्रेरणादायी एवं गौरवपूर्ण कदम होगा.

इस अवसर पर शिवसेना शहर प्रमुख अमोल माकोडे, उपजिला प्रमुख संजय पारटवार, तहसील प्रमुख नरेंद्र नरड, युवासेना तालुका प्रमुख आकाश शेंद्रे, उप तहसील प्रमुख कवलू पिंपलकर, सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. सागर माकोडे, सूरज माकोडे, आशीष गांडलेवार, राकेश भूते, अंकुश भागडकर, गणेश लांजेवार, अनुराग तोंडासे सहित बड़ी संख्या में शिवसैनिक उपस्थित थे.

बस डिपो की सफाई, फिर निकाली प्रभात फेरी

मोरभवन डिपो से स्वच्छता जागरुकता के साथ वृक्षारोपण, अधिकारी भी जुटे

संवाददाता । नागपुर

पर्यावरण संरक्षण पखवाड़े के अंतर्गत मनपा की तरफ से आज शहर के बस डिपो और बस स्टैंड की सफाई के लिए विशेष मुहिम चलाई गई, अभियान के तहत आपली बस के मोर भवन बस डिपो सहित अन्य डिपो की सफाई की गई. स्थायी समिति अध्यक्ष शिवानी दाणी ने स्वयं स्वच्छता अभियान का नेतृत्व करते हुए परिसर की सफाई की. इस अवसर पर उन्होंने प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. मुहिम अंतर्गत शनिवार को घनकचरा प्रबंधन विभाग के सफाई कर्मचारियों के साथ-साथ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, ग्रीन विजिल फाउंडेशन तथा अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के स्वयंसेवकों ने भी अभियान में हिस्सा लिया अभियान के शुभारंभ अवसर पर परिवहन व्यवस्थापक मेघना वासनकर, धरमपेठ जोन के सहायक आयुक्त राजकुमार मेश्राम, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एड. प्रकाश जायसवाल, मुख्य स्वच्छता अधिकारी डॉ. गजेंद्र महाले, प्रशासनिक अधिकारी योगेश लुंगे आदि उपस्थित थे.

मोर भवन बस डिपो सहित अन्य स्थानों पर गणमान्य व्यक्तियों द्वारा वृक्षारोपण किया गया. मनपा के परिवहन विभाग के विभिन्न आपली बस डिपो में भी अभियान चलाया गया. मोर भवन डिपो के अलावा वाठोड़ा डिपो-१, पटवर्धन डिपो, कोराडी डिपो, हिंगणा डिपो, वाठोड़ा डिपो-२, खापरी डिपो तथा वाड़ी डिपो सहित अन्य परिसरों में सफाई की गई. नागपुर महानगरपालिका के स्वच्छता अभियान के अंतर्गत अमराई क्षेत्र में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है. रविवार १४ जून को नागरिकों से अपील की गई है कि वे आमराई की सफाई के लिए अपना एक घंटा दें.

कचरा तो नजर नहीं आ रहा, झाड़ू कहां लगा रहे

पर्यावरण संरक्षण पखवाड़े के तहत चलाए जा रहे विशेष स्वच्छता अभियान अंतर्गत सफाई करते हुए स्थायी समिति अध्यक्ष शिवानी दाणी, परिवहन व्यवस्थापक मेघना वासनकर, धरमपेठ जोन के सहायक आयुक्त राजकुमार मेश्राम तथा अन्य. इस अभियान को लेकर चर्चा जोरों पर है कि साफ-सुथरे स्थानों पर ही पदाधिकारियों और अधिकारियों द्वारा झाड़ू लेकर फोटो खिंचवाते हुए देखा जा सकता है. पर झाड़ू के आसपास कहीं भी कचरा नजर नहीं आ रहा. ऐसे में लोग यह भी पूछने लगे हैं कि आखिर साफ स्थानों पर झाड़ू मारकर मनपा पदाधिकारी क्या हासिल करना चाहते हैं?

समस्याओं का जल्द होगा समाधान

देवली के जनसंवाद कार्यक्रम में डॉ. भोयर ने दिया आश्वासन

संवाददाता । वर्धा

केंद्र एवं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की जिम्मेदारी है. देवली विधानसभा क्षेत्र के नागरिकों की लंबित समस्याओं के समाधान के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह प्रतिबद्ध है और अंतिम नागरिक का निवेदन स्वीकार किए बिना यहां से नहीं जाएंगे. क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण कर जनता को न्याय दिलाया जाएगा. यह बात जिले के पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर ने कही. देवली स्थित राजे छत्रपति शिवाजी महाराज नाट्यगृह में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में संबोधित करते हुए डॉ. भोयर ने कहा कि जनता दरबार के माध्यम से नागरिकों की समस्याएं सुनकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को अधिक संवेदनशीलता के साथ कार्य करना चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि वर्षों तक काम करने के बावजूद बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर प्रशासन के पास पहुंच रहे हैं, तो यह आत्ममंथन का विषय है. सभी सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों का ईमानदारी से निर्वहन करें. कार्यक्रम में प्राप्त सभी आवेदनों एवं शिकायतों का एक माह के भीतर निपटारा करने के निर्देश भी उन्होंने अधिकारियों को दिए. इस अवसर पर विधायक राजेश बकाने, पूर्व सांसद रामदास तडस, नगराध्यक्ष किरण ठाकरे, एसपी सौरभकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्ष राहुल चोपड़ा, एसडीओ दीपक कारंडे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे. डॉ. भोयर ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य सरकार आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए लगातार प्रयासरत है.

पात्र नागरिकों को पट्टे वितरित किए जाएंः विधायक राजेश बकाने ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और पांदण मार्गों की मांग लगातार रहती है. उन्होंने अधिकाधिक पांदण मागों को मंजूरी देने, सड़कों के गड्ढों की मरम्मत तथा डामरीकरण कराने की मांग की.

लाभार्थियों को प्रमाणपत्र एवं सहायता वितरित

कार्यक्रम में पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर एवं विधायक राजेश बकाने के हाथों विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाणपत्र और सहायता वितरित की गई. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के 16 लाभार्थियों तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के माध्यम से 12 लोगों को नई राशन कार्ड प्रदान किए गए. इसके अलावा 'सभी के लिए आवास' अभियान के अंतर्गत 148 लाभार्थियों को अतिक्रमण नियमितीकरण के पट्टे तथा 50 लाभार्थियों को आवास की चाबियां वितरित की गईं. कृषि विभाग की कड़धान्य आत्मनिर्भरता अभियान योजना के तहत 5 किसानों को तूर बीज वितरण तथा 2 लाभार्थियों को पैक हाउस निर्माण के लिए अनुदान दिया गया. वहीं 10 पात्र नागरिकों को आयुष्मान कार्ड भी प्रदान किए गए.

खेत तैयार, बारिश की प्रतीक्षा

जिले में सक्रिय नहीं हुआ मानसून

संवाददाता । वर्धा

इस वर्ष समय पर बारिश होने का अनुमान जताया गया था, जिसके चलते किसान खरीफ सीजन की तैयारियों में पहले से जुट गए थे. पिछले कुछ दिनों में जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई है, लेकिन अब तक मानसून पूरी तरह सक्रिय नहीं हुआ है. जिले के अधिकांश किसानों ने खरीफ बुआई के लिए अपने खेत तैयार कर रखे हैं और वे अच्छी बारिश की प्रतीक्षा कर रहे हैं. पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2022 में जिले में सर्वाधिक औसत 1467.1 मिमी वर्षा दर्ज की गई थी, जबकि वर्ष 2023 में सबसे कम 960.02 मिमी वर्षा हुई थी.

मौसम विभाग ने इस वर्ष जिले में औसत वर्षा होने का अनुमान व्यक्त किया है. उल्लेखनीय है कि वर्ष 2025 में जिले में औसत से अधिक 1002.1 मिमी वर्षा दर्ज की गई थी. जिले के लगभग सभी राजस्व मंडलों में अतिवृष्टि हुई थी, जिससे बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी. पिछले वर्ष हुई अत्यधिक वर्षा के कारण जिले में भारी तबाही मची थी. फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा था, कई मकान और तबेले क्षतिग्रस्त हुए थे तथा अनेक पशु बाढ़ की चपेट में आ गए थे. वहीं, कई लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी थी. इस वर्ष जिले में सामान्य वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है. जिले की औसत वार्षिक वर्षा 1017.98 मिमी मानी जाती है. पिछले पांच वर्षों में वर्ष 2022, 2024 और 2025 को छोड़कर वर्ष 2021 और 2023 में औसत से कम वर्षा दर्ज की गई थी. वर्ष 2026 में जून माह के दौरान कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हुई है, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है. हालांकि, अब तक मानसून सक्रिय नहीं हुआ है. जिले के प्रमुख जलाशयों और परियोजनाओं का जलस्तर भी घटा है. दूसरी ओर, पर्याप्त वर्षा के अभाव में किसान खरीफ बुआई शुरू नहीं कर पा रहे हैं. ऐसे में किसानों सहित सभी की निगाहें अब मानसून पर टिकी हुई हैं.

अंधेरे में ST स्टैंड का प्रसाधनगृह

संवाददाता । वर्धा

शहर के बजाज चौक स्थित बस स्थानक के प्रसाधनगृह में गत कुछ दिनों से लाइट बंद पड़ा है. जिसकी वजह से प्रसाधनगृह में अंधेरा छाया रहता है. शनिवार रात दिव्यांग व्यक्ति फिसलने की घटना सामने आयी है. इसके साथ कई वृद्ध नागरिक भी फिसलकर दुर्घटना के शिकार होने की जानकारी है. देखभाल की ओर अनदेखी से संबंधित व्यवस्थापन पर रोष व्यक्त किया जा रहा है. राज्य परिवहन निगम की बस से बड़ी संख्या में नागरिक यात्रा करते हैं. ग्रामीण विभाग के नागरिक शत प्रतिशत एसटी बस पर ही निर्भर है, ऐसा भी कहा जा सकता है. यात्रियों में वृद्ध, दिव्यांग, स्कूली विद्यार्थियों की संख्या अधिक है. यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध हो इस दृष्टिकोण से सरकार ने पहल करते हुए शहर में नएं से बस स्थानक का निर्माण किया गया है. जिसपर करोड़ों रुपयों का निधि खर्च किया गया. इतना ही नहीं तो सरकार द्वारा बस स्थानक स्वच्छ व सुंदर बना रहे, इस लिए विविध उपक्रम चलाएं जाते है. बस स्थानक पर सुविधाओं की अच्छे से देखभाल होनी चाहिए, ऐसे निर्देश भी दिए गए है. फिर भी शहर के बस स्थानक स्थित प्रसाधनगृह में गत कुछ दिनों से अंधेरा छाया हुआ है. लाइट खराब होने के बाद नएं से लगाना चाहिए था. वायरींग में समस्या है, तो ठिक करने की जरूरत थी. लेकिन अनदेखी के कारण प्रसाधनगृह में अंधेरा छाया हुआ है. बस स्थानक पर शनिवार को दिव्यांग व्यक्ति फिसलने की घटना सामने आयी. इसी दौरान कई वृद्ध भी अंधेरे में टाईल्स से फिसले, ऐसा बताया जा रहा है.

स्वच्छता पुरस्कार पर उठा सवाल : हाल ही में वर्धा बस स्थानक पर 2025- 26 वर्ष में बालासाहेब ठाकरे स्वच्छ सुंदर बस स्थानक यह स्पर्धा आयोजित की थी. सफाई व सुविधाओं के विविध नामांकन इस स्पर्धा में थे. इस स्पर्धा में वर्धा नागपुर विभाग में ब गुट में द्वितीय क्रमांक मिलने की जानकारी है. किंतु, वास्तविक रूप में वर्धा बस स्थानक पर अस्वच्छता व सुविधाओं का अभाव है. जिसके चलते स्वच्छता पुरस्कार पर सवाल उठाया जा रहा है.

शहर में जल संकट, ५१ टंकियों से जलापूर्ति प्रभावित

संवाददाता / नागपुर

मनसर सब-स्टेशन में तकनीकी खराबी आने से शहर की जलापूर्ति व्यवस्था प्रभावित हो गई है। बिजली आपूर्ति बाधित होने के कारण नागोबा खेरी और गोरवाड़ा जलशोधन केंद्रों तक कच्चे पानी की पंपिंग रुक गई, जिससे शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति प्रभावित हुई।

नगर निगम के अनुसार, शहर के सभी 10 जोनों में असर पड़ा है और कुल 51 टंकियों से होने वाली जलापूर्ति बाधित हुई है। बिजली आपूर्ति बहाल होने के बाद पंपिंग दोबारा शुरू कर दी गई है, लेकिन जल वितरण व्यवस्था सामान्य होने में कुछ समय लग सकता है। लक्ष्मीनगर, धरमपेठ, हनुमान नगर, धंतोली, नेहरूनगर, गांधीबाग, सतरंजीपुरा, आसीनगर और मंगलवारी सहित कई जोनों के नागरिकों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

धान खरीदी केंद्र शुरू किए जाएं

घोड़ाम के नेतृत्व में किसानों ने दी शासन को चेतावनी

संवाददाता । आरमोरी

आरमोरी-वैरागड़ क्षेत्र के किसानों ने ग्रीष्मकालीन धान की खरीदी नहीं होने से हो रहे आर्थिक नुकसान पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रशासन से तत्काल समर्थन मूल्य पर धान खरीदी केंद्र शुरू करने की मांग की है. किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही खरीदी केंद्र शुरू नहीं किए गए तो उग्र आंदोलन किया जाएगा. यह चेतावनी सामाजिक कार्यकर्ता दिलीप घोड़ाम के नेतृत्व में किसानों ने जिला प्रशासन को दी है. किसानों का कहना है कि उन्होंने ग्रीष्मकालीन सीजन में कड़ी मेहनत कर धान का उत्पादन किया है, लेकिन शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए आवश्यक केंद्र अब तक शुरू नहीं किए गए हैं.

मृग नक्षत्र के साथ वर्षा ऋतु का आगमन हो चुका है, फिर भी मार्केटिंग फेडरेशन के अंतर्गत आरमोरी खरीदी-विक्री संस्था द्वारा आरमोरी तथा वैरागड़ में धान खरीदी केंद्र प्रारंभ नहीं किए गए हैं. वर्तमान में केवल वडधा में ही खरीदी केंद्र संचालित किया जा रहा है. वैरागड़ क्षेत्र के किसानों को अपना धान वडधा तक पहुंचाने के लिए ट्रैक्टर किराया और हमाली पर लगभग छह से सात हजार रुपये अतिरिक्त खर्च करना पड़ रहा है.

ऐसे में किसानों को धान अपने घरों में ही संग्रहित रखना पड़ रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. किसानों ने आरोप लगाया कि आरमोरी तथा वैरागड़ में खरीदी केंद्र शुरू करने की मांग बार-बार किए जाने के बावजूद प्रशासन गोदाम उपलब्ध नहीं होने का कारण बता रहा है. किसानों का कहना है कि यह बहाना बनाकर धान खरीदी प्रक्रिया में जानबूझकर देरी की जा रही है. वर्षा शुरू होने से घरों में रखा धान खराब होने का खतरा बढ़ गया है, जिसके कारण किसानों को मजबूरन निजी व्यापारियों को कम कीमत पर धान बेचने की नौबत आ रही है. किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि अगले दो दिनों के भीतर खरीदी केंद्र शुरू करने को लेकर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो किसानों के साथ जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष उग्र आंदोलन किया जाएगा. इस अवसर पर वी. डी. बावनकर, हेमराज प्रधान, राजकुमार नदरधने, विशाल काबई, मोहन धनकर, नकुल सोनबावणे, सुनील कुमरे, राजू मेत्राम, प्रीतम मेत्राम, विजय मैत्राम सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे.

शंकरपुर व सावरहेटी में शराब बिक्री

संवाददाता / चामोर्शी

शहर मुख्यालय से कुछ दूरी पर होनेवाले शंकरपुर व सावरहेटी गांव में अवैध शराब बिक्री बढ़ गई है. जिससे गांव की सामाजिक शांतता भंग हो रही है. खासकर महिलाओं को काफी परेशानी हो रही है.

जिससे इस शराब बिक्री के खिलाफ मुहिम चलाते हुए स्थानीय महिलाओं ने स्वाभिमानी सामाजिक संगठना के नेतृत्व में चामोर्शी पुलिस थाने पर दस्तक देकर अवैध शराब बिक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई करते हुए शराब बिक्री पर पाबंदी लागू करने की मांग की. तहसील मुख्यालय समिप होने वाले शंकरपुर व सावरहेटी इस गांव में अवैध शराब की बिक्री बढ़ गई है. इस शराब बिक्री के खिलाफ शंकरपुर व सावरहेटी इस गांव की महिलाओं ने एल्गार करते हुए सीधे चामोर्शी पुलिस थाने पर दस्तक दी. गांव के शराब बिक्रेताओं पर तत्काल कडी कार्रवाई करते हुए गांव से शराब बाहर करे, ऐसी मांग करते हुए महिलाओं ने थानेदार दिपक डोंब को ज्ञापन सौंपा. इस समय स्वाभिमानी सामाजिक संगठना के अध्यक्ष राजू धोंडरे, माणिकराव कोहले, रमेश येडलावार, शिवसेना के यशवंत कत्रोजवार, शालिनी मंडपल्लीवार, मंगला धोंडरे, लता रोहणकर, अरुणा रोहणकर, सुनंदा यदुनवार, कल्पना राऊत, नीता रोहणकर, सरिता मडावी, अल्का व्याहाडकर, मालन गेडाम, मनीषा बावणे, सोनी बावणे, पुष्पा पोटे, अर्चना कासेवार कविता म्हशाखेत्री, वंदना मानपाल्लीवर, संध्या रोहणकर, भूमिका चौधरी आदि महिलाएं उपस्थित थे.

फिटनेस व पर्यावरण सुरक्षा का दिया संदेश

वर्धा : स्थानीय जिला पुलिस द्वारा रविवार सुबह आयोजित की गई 'संडे ऑन साइकिल' साइकिल उपक्रम को शहरवासियों का भारी प्रतिसाद मिला. पुलिस मुख्यालय से सुबह 6 बजे शुरू हुई इस उपक्रम में बड़ी संख्या में नागरिकों, युवाओं, महिलाओं, बच्चों तथा विभिन्न साइकिलिंग क्लबों के सदस्यों ने सहभागिता दर्ज कराई. कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और फिटनेस को बढ़ावा देना था. यह विशेष उपक्रम वर्धा के पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार अग्रवाल की संकल्पना एवं मार्गदर्शन में आयोजित किया गया. उपक्रम में वर्धा पुलिस दल के वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई. सफेद गणवेश में उपस्थित पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों का उत्साह बढ़ाया और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया. उपक्रम में शहर के विभिन्न साइकिलिंग क्लबों के सदस्य, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और छोटे बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया. प्रतिभागियों ने आकर्षक साइकिलिंग जर्सी और सुरक्षा हेलमेट पहनकर उपक्रम को विशेष रंग प्रदान किया. 'स्वस्थ रहें, साइकिल चलाएं' तथा 'पर्यावरण बचाएं' जैसे संदेशों के साथ उपक्रम शहर के प्रमुख मार्गों से होकर निकाली गई. नागरिकों ने मार्ग में जगह-जगह उपक्रम का स्वागत कर प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया. कार्यक्रम के सफल आयोजन में यातायात शाखा के पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल, रिजर्व पुलिस निरीक्षक तथा कल्याण शाखा के सहायक पुलिस निरीक्षक आशीष चिलांगे सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

बोरी-चातारी पहुंची खनन की टीम

अवैध उत्खनन की जांच शुरू

संवाददाता । उमरखेड़

पैनगंगा नदी के बोरी-चातारी रेत घाट पर बड़े पैमाने पर हुए कथित अवैध रेत उत्खनन की शिकायतों के बाद आखिरकार जिला खनन विभाग की टीम ने शुक्रवार को मौके का निरीक्षण किया.

रेत घाट की अवधि समाप्त होने के बाद जिला खनन कार्यालय के भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) सहायक धनाजी जाधव अपनी टीम के साथ सुबह-सुबह बोरी-चातारी रेत घाट पहुंचे और नदी पात्र का जायजा लिया. पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि विदर्भ-मराठवाड़ा सीमा क्षेत्र से बहने वाली पैनगंगा नदी के बोरी-चातारी क्षेत्र में स्थानीय अधिकारियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर अवैध रेत उत्खनन किया गया. पिछले तीन से चार महीनों से इस संबंध में राजस्व विभाग को लगातार शिकायतें दी जा रही थीं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. बताया जाता है कि 30 मार्च को एलसीबी द्वारा रेत उत्खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का प्रयास किया गया था, लेकिन राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते मामला चर्चा का विषय बन गया. इसके बाद राजस्व प्रशासन और रेत माफिया की कथित साठगांठ से अवैध रेत तस्करी लगातार जारी रही. शिकायतों के बावजूद किसी अधिकारी ने कार्रवाई करने का साहस नहीं दिखाया. 10 जून को रेत घाट की अवधि समाप्त हो गई. इसी बीच 11 जून को नहर का पानी नदी में छोड़ा गया, लेकिन बोरी क्षेत्र तक पानी नहीं पहुंचा. इससे रेत चोरी के निशान दिखे.

प्रशासन ने की अफवाहों पर विश्वास न रखने की अपील

संवाददाता । वर्धा

अमेरिका-ईरान संघर्ष के चलते खाड़ी देशों आने कच्चे तेल के आयात पर संभावित प्रभाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने एक व्यक्ति को अधिकतम 200 लीटर डीजल की बिक्री का निर्णय लिया है. खरीफ सीजन के ऐन पहले लिए गए इस निर्णय को लेकर किसानों और ट्रैक्टर संचालकों में चर्चा का माहौल है. हालांकि जिला प्रशासन का कहना है कि जिले में डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और खेती-किसानी के कार्यों पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ रहा है.

जिले के किसान खरीफ सीजन की तैयारियों में जुटे हुए हैं. कृषि विभाग के अनुसार इस वर्ष जिले में लगभग 4 लाख 18 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में कपास, सोयाबीन और तुअर सहित विभिन्न खरीफ फसलों की बुआई होने का अनुमान है. हालांकि अब तक जिले में बुआई योग्य पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है. अच्छी बारिश होने के बाद किसान बड़े पैमाने पर बुआई कार्य शुरू करेंगे. कुछ किसानों ने जोखिम उठाते हुए कपास की सूखी बुआई भी कर दी है. समय और लागत की बचत के लिए अधिकांश किसान ट्रैक्टरों की सहायता से खेत तैयार कर रहे हैं. ऐसे में डीजल बिक्री की सीमा को लेकर चिंता व्यक्त की जा रही थी, लेकिन किसानों और ट्रैक्टर मालिकों का कहना है कि वर्तमान में जिले में डीजल की कोई कमी नहीं है और कृषि कार्य सामान्य रूप से जारी हैं.

योग्य नियोजन से बढाएं कृषि उत्पादन

वर्धा : कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा 'खेत बचाओ अभियान' चलाकर जिले के विभिन्न गांवों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए अभिनव पहल की जा रही है. इस अभियान के अंतर्गत वर्धा, बोरगांव, आमला और रत्नापुर में किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए. प्रशिक्षण कार्यक्रम में वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. जीवन कतोरे ने कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन प्राप्त करने की विभिन्न तकनीकों की जानकारी दी.

उन्होंने खरीफ फसलों के उचित प्रबंधन पर मार्गदर्शन करते हुए किसानों को अपनी भूमि की ज्ञ जांच तथा पोषक तत्वों के विश्लेषण का महत्व समझाया. उन्होंने कहा कि इससे किसानों को अपनी भूमि की वास्तविक आवश्यकता का पता चलता है और उसी के अनुसार उर्वरकों का संतुलित उपयोग किया जा सकता है. डॉ. कतोरे ने मिट्टी में जैविक कार्बन बढ़ाने के लिए वर्मी कम्पोस्ट तथा ढँचा जैसी हरी खादों के उपयोग की सलाह दी. इसके अलावा पानी की बर्बादी रोकने के लिए ड्रिप सिंचाई पद्धति अपनाने पर जोर दिया. उन्होंने वर्षा जल संचयन एवं खेत तालाबों के माध्यम से पानी का संरक्षण करने की आवश्यकता भी बताई. अभियान के दौरान किसानों को बताया गया कि पीडीकेवी अंबा जैसी अधिक उत्पादन देने वाली सोयाबीन किस्मों के उपयोग से खेती की लागत कम होती है और स्थायी लाभ प्राप्त करने में सहायता मिलती है. साथ ही रासायनिक कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से बचते हुए नीम अर्क तथा मित्र कीटों की सहायता से सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण फसल उत्पादन करने का आह्वान किया गया. इस अभियान को रत्नापुर के सरपंच सुधीर बोबडे, आमला के पूर्व सरपंच विठ्ठल इंगले, ग्रामसेवक सुधीर भोसले, कृषि ताई नीता होरे, वैभव चौधरी तथा प्रगतिशील किसान उल्हास जैन का सहयोग प्राप्त हुआ, ऐसी जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से दी गई.

चक्काजाम आंदोलन, वडसा-अर्जुनी सड़क के मरम्मत की मांग

सड़क मरम्मत के लिए विधायक सड़क पर

संवाददाता / देसाईगंज

वडसा से अर्जुनी महत्वपूर्ण तथा व्यस्त मार्ग है, लेकिन यह तक जानेवाला मार्ग परिसर का व्यापक मार्ग पिछले कई महीनों से बदहाल स्थिति में है. सड़क पर बने बड़े-बड़े गड्ढों के कारण आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

सड़क की मरम्मत की मांग को लेकर कई बार सरकार तथा संबंधित विभागों से आग्रह किए जाने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर विधायक रामदास मसराम के नेतृत्व में वडसा-अर्जुनी टी-पॉइंट पर चक्काजाम आंदोलन किया गया. आंदोलन में क्षेत्र के किसान, विद्यार्थी, व्यापारी, वाहन चालक, महिलाएं तथा विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए. सड़क की खराब स्थिति के कारण बढ़ रही दुर्घटनाओं पर नागरिकों ने तीव्र नाराजगी व्यक्त की. आंदोलन के दौरान 'सड़क मरम्मत के लिए तत्काल निधि मंजूर करो', 'गड्ढामुक्त सड़कें दो' तथा 'विकास के वादे नहीं, अच्छी सड़कें चाहिए' जैसे नारों से पूरा परिसर गूंज उठा. इस दौरान विधायक रामदास मसराम ने कहा कि वडसा अर्जुनी मार्ग हजारों नागरिकों के दैनिक आवागमन का प्रमुख मार्ग है.

इस सड़क का उपयोग छात्र, किसान, व्यापारी तथा शासकीय कर्मचारी बड़ी संख्या में करते हैं. सड़क की व्यापक दयनीय स्थिति के कारण लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर यात्रा करनी पड़ रही है. गड्ढों के कारण वाहनों को नुकसान हो रहा है और दुर्घटनाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है. ऐसी बात कहीं. इसआंदोलन में कांग्रेस के देसाईगंज तहसील अध्यक्ष राजेंद्र बुल्ले, कांग्रेस के आरमोरी तहसील अध्यक्ष मिलिंद खोब्रागड़े, पूर्व उपसभापति नितीन राऊत, कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष दिलीप घोड़ाम, पूर्व जिला परिषद सदस्य जयमाला पेंदाम, पूर्व नगराध्यक्ष शालु दंडवते, गुटनेता विकास प्रधान सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और सैकड़ों नागरिक उपस्थित थे.

बजट मंजूर कराकर होगा निर्माण

आंदोलन के कारण कुछ समय के लिए वडसा अर्जुनी मार्ग पर यातायात प्रभावित रही. हालांकि पुलिस प्रशासन की उपस्थिती में आंदोलन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ. इस दौरान लोकनिर्माण के अधीक्षक ठाकरे ने आश्वासन दिया कि शुरू वित्तीय वर्ष के बजट में निधि मंजूर कर सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्य पूरा जाएगा. इस आश्वासन के बाद विधायक रामदास मसराम के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया. विधायक मसराम ने स्पष्ट किया कि यदि निधि मंजूर नहीं की गई तो यह संघर्ष आगे भी जारी रहेगा.

दो वर्षों से शोपीस बनी हुई है जल जीवन मिशन की टंकी

प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठ रहे सवाल, कागजों में सिमटकर रह गई है योजना

संवाददाता / गोंदिया/तिरोड़ा

तहसील के ग्राम फत्तेपुर में पिछले कई दिनों से पेयजल संकट गहराता जा रहा है. भीषण गर्मी और जल स्रोतों के घटते जल स्तर के कारण ग्रामीणों को पानी के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है. गांव में जल जीवन मिशन योजना के तहत करीब दो वर्ष पूर्व बनाई गई नई पानी की टंकी, बोरवेल और पाइपलाइन व्यवस्था आज भी शुरु नहीं हो सकी है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी व्याप्त है.

ग्रामीणों के अनुसार, जल जीवन मिशन के तहत गांव में लाखों रु. खर्च करके पानी की टंकी का निर्माण किया गया है. इसके साथ ही बोरवेल खोदे गए और घर-घर तक पाइप लाइन बिछाकर नल कनेक्शन भी दिए गए. इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाना था, लेकिन निर्माण कार्य पूरा होने के बावजूद आज तक ग्रामीणों को एक बूंद पानी भी नसीब नहीं हुआ है.

समाजसेवी धनंजय रिनायत का आरोप है

कि, संबंधित विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार की लापरवाही के कारण यह महत्वाकांक्षी योजना सिर्फ कागजों तक सीमित होकर रह गई है. उनका कहना है कि करोड़ों नहीं तो लाखों रु. की सरकारी निधि खर्च होने के बाद भी ग्रामीणों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, जिससे सरकारी धन के दुरुपयोग की आशंका भी जताई जा रही है. ग्रामीणों का कहना है कि गर्मी के मौसम में पानी की समस्या और अधिक गंभीर हो जाती है. कई परिवारों को दूर-दराज के जल स्रोतों से पानी लाना पड़ रहा है, जबकि गांव में सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद जलापूर्ति शुरु नहीं की जा रही है. इससे महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. धनंजय रिनायत ने संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से तत्काल हस्तक्षेप कर योजना की तकनीकी और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि यदि समय रहते जलापूर्ति शुरु नहीं की गई तो ग्रामीणों के साथ आंदोलन करने पर भी विचार किया जाएगा.

ग्रामीणों ने भी प्रशासन से मांग की है कि जल जीवन मिशन योजना की जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए तथा जल्द से जल्द गांव में नियमित पेयजल आपूर्ति शुरु की जाए, ताकि फत्तेपुर के नागरिकों को पानी की समस्या से राहत मिल सके.

भीषण गर्मी के बीच रजेगांव गांव में पिछले पांच दिनों से पेयजल आपूर्ति पूरी तरह बंद होने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. गांव की मुख्य जलापूर्ति पाइपलाइन एक निजी कार्य के दौरान क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके कारण पूरे गांव का पानी बंद हो गया. घटना के चार दिन बीत जाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ती जा रही है.

जानकारी के अनुसार, गांव में चल रहे एक निजी निर्माण कार्य के दौरान मुख्य पाइप लाइन टूट गई. इसके बाद गांव की नियमित जलापूर्ति बाधित हो गई. लगभग ढाई हजार की आबादी वाले रजेगांव में लोग पीने के पानी के लिए इधर-उधर भटकने को मजबूर हैं. भीषण गर्मी के कारण स्थिति और गंभीर हो गई है तथा महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है. ग्रामीणों का कहना है कि चार दिनों से पानी नहीं आने के बावजूद प्रशासन द्वारा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है. शासन स्तर पर ऐसी आपात स्थितियों में तत्काल वैकल्पिक जलापूर्ति की व्यवस्था करने के निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन रजेगांव में अब तक टैंकर या अन्य किसी माध्यम से पानी उपलब्ध नहीं कराया गया है. इससे ग्राम पंचायत प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं. ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि. गांव की विभिन्न समस्याओं पर आवाज उठाने वाला विपक्ष भी इस गंभीर मुद्दे पर मौन बना हुआ है. नागरिकों का कहना है कि पेयजल जैसी मूलभूत समस्या को लेकर जनप्रतिनिधियों और विपक्ष को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए थी, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल दिखाई नहीं दी है. गांव में पहले से ही कई नागरिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं लंबित हैं. ऐसे में जलापूर्ति बंद होने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं. ग्रामीणों का कहना है कि गांव में स्थायी ग्रामसेवक या जिम्मेदार अधिकारी की नियुक्ति नहीं होने के कारण अधिकांश कार्य प्रभारी अधिकारियों के भरोसे चल रहे हैं, जिससे विकास कार्य और जनसुविधाएं प्रभावित हो रही हैं.

ग्रामीणों ने क्षतिग्रस्त पाइपलाइन की तत्काल मरम्मत कर नियमित जलापूर्ति शुरु करने, वैकल्पिक रूप से टैंकरों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की है. साथ ही रजेगांव जैसे बड़े गांव के लिए पूर्णकालिक अधिकारी नियुक्त करने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है.

केशोरी ग्रामसभा में निकाला आरक्षण ड्रॉ

संवाददाता / केशोरी

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार वर्ष 2024, 2025 एवं 2026 में कार्यकाल समाप्त होने वाली ग्राम पंचायतों के आम चुनावों के लिए सदस्यों के आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया के तहत केशोरी ग्राम पंचायत में विशेष ग्रामसभा का आयोजन किया गया. ग्राम पंचायत कार्यालय में आयोजित सभा में पांच वार्डों के 13 सदस्य पदों के लिए आरक्षण ड्रॉ निकाला गया.

ड्रॉ के अनुसार, वार्ड क्रमांक 1 में एक अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) पुरुष, एक अनुसूचित जनजाति (एसटी) महिला तथा एक सामान्य महिला सदस्य का आरक्षण

निर्धारित किया गया. वार्ड क्रमांक 2 में एक सामान्य वर्ग तथा एक अनुसूचित जनजाति महिला के लिए सीट आरक्षित की गई. वार्ड क्रमांक 3 में एक सामान्य वर्ग सदस्य और एक अनुसूचित जाति (एससी) महिला के लिए आरक्षण तय किया गया. इसी प्रकार वार्ड क्रमांक 4 में एक अनुसूचित जनजाति पुरुष, एक सामान्य वर्ग सदस्य तथा एक सामान्य महिला के लिए आरक्षण घोषित किया गया. वहीं वार्ड क्रमांक 5 में एक सामान्य वर्ग सदस्य, एक अन्य पिछड़ा वर्ग महिला तथा एक सामान्य महिला के लिए सीट आरक्षित की गई है. ग्राम पंचायत प्रशासन ने बताया कि सरपंच पद के लिए पूर्व में ही सामान्य महिला वर्ग का आरक्षण घोषित किया जा चुका है. आरक्षण ड्रॉ प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आगामी ग्राम पंचायत चुनावों को लेकर संभावित उम्मीदवारों एवं ग्रामीणों में उत्सुकता बढ़ गई है.

इस अवसर पर मंडल अधिकारी पुंडलिक कुंभरे, राजस्व अधिकारी विजय निमकर, ग्राम पंचायत प्रशासक नंदकुमार गहाणे, जिला परिषद सदस्य श्रीकांत घाटबांधे, पंचायत समिति सदस्य घनश्याम धामट, विमुस अध्यक्ष अनिल लाडे, ग्राम विकास अधिकारी प्रेमानंद नगराले, चेतन दहीकर, श्रीराम शेंडे, विलास गायकवाड़, विनोद गहाणे समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे.

विदर्भ के सभी स्कूल २६ जून से ही खुलेंगे

संवाददाता / सालेकसा

विदर्भ में स्कूलों के शुरु होने की तारीख को लेकर दायर याचिका पर 10 जून को मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई. न्या. अनिल किल्लोर और राजेश वाकोडे की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की.

सुनवाई के दौरान शिक्षा संचालनालय द्वारा 9 जून को जारी किए गए 22 जून से स्कूल शुरु करने संबंधी परिपत्र को राज्य सरकार की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत किया गया. सरकारी पक्ष ने इसी के अनुरुप आदेश देने का अनुरोध किया.

लेकिन, याचिकाकर्ता महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति की ओर से अधिवक्ता डॉ. जी. बी. कुलकर्णी ने सरकार के रुख का विरोध किया. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने सरकार की भूमिका पर असहमति जताई. इसके बाद न्यायालय ने विदर्भ में स्कूलों को 15 जून अथवा 22 जून से शुरु करने संबंधी शिक्षा संचालक के आदेशों को रद्द कर दिया. साथ ही, 20 अप्रैल 2023 के सरकारी निर्णय के अनुसार ही स्कूल शुरु करने के निर्देश दिए. इस फैसले के बाद स्पष्ट हो गया है कि विदर्भ के स्कूल पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 26 जून से ही शुरू होंगे. सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समिति के पदाधिकारी विजय कोंबे, लीलाधर ठाकरे, गोकुलदादा राऊत, प्रमोद सुरोसे, प्रकाश सव्वालाखे, प्रशांत निंभोरकर तथा काजणे उपस्थित थे.

हाईकोर्ट के इस निर्णय से विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच स्कूल खुलने की तारीख को लेकर बना संशय समाप्त हो गया है। अब विदर्भ में नया शैक्षणिक सत्र 26 जून से ही प्रारंभ होगा.

गोरेगांव तहसील भाजपा युवा मोर्चे की कार्यकारिणी घोषित

संवाददाता / गोरेगांव

भारतीय जनता युवा मोर्चा की गोरेगांव तहसील की नई कार्यकारिणी की घोषणा जिला अध्यक्ष रोहित अग्रवाल के मार्गदर्शन में की गई. नई कार्यकारिणी में तहसील अध्यक्ष रविंद्र (रवि) पटले के नेतृत्व में युवा कार्यकर्ताओं को विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गई.

कार्यकारिणी में भाजयुमो गोरेगांव मंडल के महामंत्री पद पर किरण पालेवार, अजय राहंगडाले और खोमेंद्र पारधी की नियुक्ति की गई है. इस अवसर पर रोहित अग्रवाल ने कहा कि युवाल संगठन की सबसे बड़ी ताकत हैं. युवाओं के सहयोग से गोरेगांव तहसील में संगठन को और अधिक मजबूत बनाया जाएगा तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा.

इस बैठक में नवनियुक्त पदाधिकारियों से बूथ सशक्तिकरण, सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी, पर्यावरण संरक्षण, युवाओं को संगठन से जोड़ने तथा आगामी चुनावों में भाजपा की विजय सुनिश्चित करने के लिए समर्पित भाव से कार्य करने का आह्वान किया गया.

कार्यक्रम में पूर्व विधायक हेमंत पटले, डॉ. लक्ष्मण भगत, पंस सभापति चित्रकला चौधरी, जिला महामंत्री मनोज बोपचे, पुष्पराज जनबंधु, अभय मानकर, विक्की बघेले, अजीत टेंभरे समेत भाजपा, भाजयुमो के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे.

निधि के अभाव में थमा आवास का निर्माणकार्य

संवाददाता / केशोरी

सरकार की आवास योजना के तहत अपना पक्का घर बनाने का सपना देख रहे लाभार्थियों को इन दिनों भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बारिश का मौसम शुरु होने से पहले ही दूसरे चरण की राशि नहीं मिलने के कारण कई आवासों का निर्माण कार्य स्लैब स्तर पर ही अटक गया है. इससे लाभार्थियों में नाराजगी बढ़ रही है और वे सवाल उठा रहे हैं कि आखिर आवास योजना की अगली किश्त का चेक कब मिलेगा.

केशोरी क्षेत्र में लगभग 15 आवासों का निर्माण कार्य जारी है. अधिकांश लाभार्थियों ने पहली किश्त से दीवारें और स्लैब तक का काम पूरा कर लिया है, लेकिन दूसरी किश्त की राशि अब तक प्राप्त नहीं होने के कारण आगे का निर्माण पूरी तरह ठप पड़ गया है. इससे लाभार्थियों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है.

आवास का निर्माण पूरा करने के लिए कई लोगों ने कर्ज लिया है, जबकि कुछ ने मजदूरी करके पैसे जुटाए हैं. ऐसे में अगली किश्त न मिलने से वे आगे का निर्माण कार्य

नहीं कर पा रहे हैं. लाभार्थियों को यह भी डर सता रहा है कि बारिश शुरु होने पर अधूरे निर्माण को नुकसान पहुंच सकता है.

कई लाभार्थी अभी भी किराए के मकानों या अन्य लोगों के घरों में रहने को मजबूर हैं. उनका उद्देश्य बारिश से पहले अपने नए घर में प्रवेश करने का था, लेकिन निधि के अभाव में यह सपना अधूरा रह गया है. दूसरी ओर खरीफ सीजन के कृषि कार्य शुरु होने से खेती और घर निर्माण दोनों की जिम्मेदारियां संभालना उनके लिए मुश्किल हो गया है. लाभार्थियों का कहना है कि यदि शासन समय पर राशि उपलब्ध नहीं कराएगा तो योजना का उद्देश्य ही प्रभावित हो जाएगा. उन्होंने प्रशासन से तत्काल दूसरी किश्त जारी करके निर्माण कार्यों को पूरा कराने की मांग की है. लाभार्थी कोमल शेंडे, नरेश शेंडे, प्रमिला मानकर, वंदना मानकर, कमल उईके, भोजू मेश्राम और धनराज मेश्राम ने जल्द राशि वितरित नहीं करने पर तहसील कार्यालय के सामने आमरण अनशन करने और आंदोलन की चेतावनी दी है.

शाखा अभियंता हर्षवर्धन बोरकर ने बताया कि शासन की ओर से निधि प्राप्त हो चुकी है, लेकिन वह फिलहाल एफडी (फिक्स्ड डिपॉजिट) के रूप में है. जब तक एफडी क्लियर नहीं हो जाती, तब तक लाभार्थियों को चेक जारी नहीं किए जा सकते. उन्होंने कहा कि प्रक्रिया पूरी होते ही राशि वितरित कर दी जाएगी.

लोहार समाज के दसवीं-बारहवीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों का सम्मान

संवाददाता / गोंदिया

विश्वकर्मा लोहार समाज संगठन बचत समूह द्वारा लोहार समाज के उन विद्यार्थियों का सम्मान किया गया, जिन्होंने वर्ष 2025-26 में दसवीं एवं बारहवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। यह सम्मान समारोह बुधवार (ता. 10) को भगवान विश्वकर्मा मंदिर सभागृह, भानपुर में आयोजित किया गया।

कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेश सोनवाने ने की। मुख्य अतिथियों के रूप में रवि मेश्राम, डिलेश्वर पंधराम, राजेंद्र बावने, राकेलाल मेश्राम, चिंतेश बावने तथा अरविंद काले उपस्थित थे।

लोहार समाज के अनेक

विद्यार्थी दसवीं उत्तीर्ण करने के बाद आर्थिक परिस्थितियों के कारण आगे की पढ़ाई छोड़कर अपने माता-पिता के कार्यों में सहयोग करने लगते हैं। मार्गदर्शन के अभाव में वे कठिन जीवन व्यतीत करते हैं। उन्हें उचित मार्गदर्शन मिले और समाज शिक्षित बने, इस उद्देश्य से लोहार समाज संगठन विद्यार्थियों का सम्मान कर उन्हें मार्गदर्शन देने का कार्य कर रहा है, ऐसी जानकारी कार्यक्रम के अध्यक्ष राजेश सोनवाने ने अपने संबोधन में दी। उन्होंने सभी विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे आर्थिक कठिनाइयों का सामना करते हुए भी दसवीं और बारहवीं के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त करें तथा समाज की प्रगति में योगदान दें।

शिक्षा के लिए समाज को प्रोत्साहित करने का कार्य पूरे जिले में शुरू किया गया है। जिले में लोहार समाज युवा संगठन का गठन किया जाएगा, इसलिए युवाओं से आगे आकर सहयोग करने का आग्रह चिंतेश बावने ने किया। आगे की शिक्षा को बढ़ावा देने और समाज को शिक्षित बनाने के उद्देश्य से गोंदिया जिले के विभिन्न तहसीलों में दसवीं और बारहवीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों का मोमेंटो एवं प्रमाणपत्र देकर सम्मान समारोह आयोजित किया जा रहा है।

गोंदिया तहसील के जानवी उके, मनीषा कटरे, शालिनी सोनवाने, पियुष मेश्राम, धीरज बावने, कशिश साऊसकार, याचना सोनवाने, शीतल उके, कृष्णा मेश्राम, गौरव बागड़े, आशीष बावने तथा अंजना सोनवाने को मोमेंटो और प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम का संचालन योगराज बावने ने किया तथा आभार प्रदर्शन मुन्नालाल मेश्राम ने किया। कार्यक्रम की सफलता के लिए बचत समूह के सदस्यों एवं समाज बंधुओं ने सहयोग प्रदान किया।

मोदी सरकार के १२ वर्षों के कार्यकाल में देश सहित गोंदिया का कायापलट - विधायक डॉ. फुके

भाजपा की पत्रकार परिषद

संवाददाता / गोंदिया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के ऐतिहासिक 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों की जानकारी देने के लिए आज 14 जून को स्थानीय राइस मिलर्स एसोसिएशन के सभागार में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर पत्रकारों से संवाद करते हुए विधायक डॉ. परिणय फुके ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न केवल वैश्विक स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ाया है, बल्कि बुनियादी ढांचे के विकास, गरीब कल्याणकारी योजनाओं, नक्सलवाद के सफल उन्मूलन और आदिवासी क्षेत्रों के विकास के माध्यम से महाराष्ट्र तथा गोंदिया

जिले की प्रगति को नई गति दी है। मोदीजी का यह दूरदर्शी विजन आज वास्तविक धरातल पर दिखाई दे रहा है और विकसित भारत की इस संकल्पना में गोंदिया जिला पूरी ताकत के साथ अपना योगदान दे रहा है। इस पत्रकार परिषद में विधायक विजय रहांगडाले, विधायक विनोद अग्रवाल, पूर्व विधायक केशवराव मानकर, भाजपा जिलाध्यक्ष सीताताई रहांगडाले, भंडारा-गोंदिया जिला समन्वयक वीरेंद्र अंजनकर, महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री रचनाताई गहाणे, जिला महामंत्री पंकज रहांगडाले, सुनील केलनका, नरेंद्र बाजपेयी, पंचायत समिति सभापति मुनेश रहांगडाले, छत्रपाल तुरकर प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

पत्रकार परिषद में विधायक डॉ. परिणय फुके ने मोदी सरकार की क्षेत्रवार उपलब्धियों के आधिकारिक आंकड़े प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि 2014 में जनता ने मोदी पर विश्वास जताया और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने सबसे पहले 'पीएम किसान सम्मान निधि' की फाइल पर हस्ताक्षर कर किसानों और गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। सरकार की पारदर्शी नीतियों के कारण पिछले कुछ वर्षों में देश के लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। तकनीक और सीधे बैंक खातों में धनराशि हस्तांतरित करने वाली सुशासन व्यवस्था के कारण सरकारी खजाने के लगभग 4.31 लाख करोड़ रुपये की बचत हुई है। आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर सरकार की दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण आज देश नक्सलवाद से मुक्त हो गया है और पहले का 'रेड कॉरिडोर' अब 'ग्रीन ग्रोथ ज़ोन' में परिवर्तित हो गया है।

जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए विधायक फुके ने बताया कि जनधन योजना के अंतर्गत 58 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं, जिनमें 32 करोड़ से अधिक खाते महिलाओं के हैं। इसके अलावा कोविड काल से 81 करोड़ नागरिकों को मुफ्त राशन, आयुष्मान भारत के अंतर्गत 60 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त उपचार हेतु स्वास्थ्य कार्ड, और आवास योजना के माध्यम से 4 करोड़ से अधिक परिवारों को पक्के घर दिए गए हैं। उज्ज्वला योजना के माध्यम से 11 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस, जल जीवन मिशन के अंतर्गत 16 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल का पानी और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। कृषि क्षेत्र के लिए पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 11 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में सीधे 4.3 लाख करोड़ रुपये जमा किए गए हैं, जबकि 'लखपति दीदी' योजना के अंतर्गत 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है।

बुनियादी ढांचे के विकास के बारे में विधायक फुके ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गांवों में लगभग 8 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई गईं, जिनमें से 4 लाख किमी सड़कें केवल पिछले 12 वर्षों में बनाई गई हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों का नेटवर्क 2014 के 91,287 किमी से बढ़कर आज 1.46 लाख किलोमीटर से अधिक हो गया है और सड़क निर्माण की गति प्रतिदिन 34 किमी तक पहुंच गई है। रेलवे का 99.6इ से अधिक विद्युतीकरण पूरा हो चुका है और देशभर में 164 से अधिक 'वंदे भारत एक्सप्रेस' चल रही हैं। देश में हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 164 के पार पहुंच गई है। वैश्विक स्तर पर 'वैक्सीन मैत्री' के माध्यम से 99 देशों को दवाइयां उपलब्ध कराकर और 70 लाख करोड़ रुपये से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (इ३ध) आकर्षित कर भारत ने नया इतिहास रचा है। 'मॉर्निंग कंसल्ट' के अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 75इ समर्थन प्राप्त हुआ है, जिससे वे दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं और यह प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व की बात है, ऐसा विधायक फुके ने कहा।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक चंद्रकांत खंडेलवाल द्वारा भवानी प्रिंटींग प्रेस, गुरूनानक वॉर्ड, गोंदिया - 441601 (महाराष्ट्र) से मुद्रित कर गुरूनानक वार्ड, गोंदिया - 441601 (महाराष्ट्र) से प्रकाशित.
संपादक :- चंद्रकात खंडेलवाल, पी.आर.पी एक्ट के तहत जिम्मेदार *